>

Title: Need to streamline and decentralize the functions of National Disaster Management Commission set up to meet the challenges posed by natural calamities in the Country.

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, जब सुनामी आई थी, तब उसके बाद इसी सदन में प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए और उससे बचाव के लिए एक बिल पास हुआ था और उसमें एक आयोग का गठन किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, उस राष्ट्रीय आयोग ने अब काम करना तो शुरु कर दिया है लेकिन पिछले दिनों जब बिहार, असम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ से बचने के प्रबन्धन में या बाढ़ आने पर जो आपदा प्रबन्धन होना चाहिए था, वह पूरी तरह नहीं हो सका। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो आपदा प्रबन्धन से संबंधित, नैचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए जो आयोग बनाया गया, क्या उसका विकेन्द्रीयकरण राज्यों और जिलों तक करने का सरकार का कोई विचार है क्योंकि बिहार के 17 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित रहते हैं और हर बार यह बाढ़ आने के बाद ये बातें उठती हैं और जब तक प्रबन्धन की बातें चलती हैं, तब तक बाढ़ चली जाती है। इस बार 3-3 महीने, 2-2 महीने तक बाढ़ का पानी खड़ा रहा लेकिन बचाव कार्य में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या उससे बचाव के लिए प्रीवेंटिव एक्शन के लिए यानी प्राकृतिक आपदा आने से पहले, â€¦(व्यवधान) सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बाढ़ से बचने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए। आपदा आने के बाद प्रबन्धन का बहुत ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए।

लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि क्या जिला स्तर के आयोग का विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा? पिछले दिनों दो आयोगों की बहाली की जा चुकी है लेकिन बिहार हमेशा बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहता है लेकिन वहां आयोग की बहाली नहीं की गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि बिहार में भी विकेन्द्रीयकरण किया जाये और लोगों को बचाया जाये।